(ग) पहली नवम्बर, 1979 को जब चालू तेल वर्ष आरम्भ हुआ, लगभग 2.19 लाख मीटरी टन।

(घ) मांग तथा देश में खाद्य तेलों की उपलभ्यता के बीच के अन्तर को प्रभावी ढंग से दूर करने के लिये खाद्य तेलों की पर्याप्त मात्रा का आयात जारी रखने का प्रस्ताव है, ताकि विभिन्न उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा किया जा सके। तेल वर्ष 1979-80 के दौरान आयात की ठीक-ठीक मात्रा इन बातों पर निर्भर करेगी—देश में तेलों का उत्पादन स्तर, देश में तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य रुख, विदेशी मुद्रा की उपलभ्यता तथा अन्य संगत बातें। इसके अलावा, देश मे खाद्य तिलहनों और तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिये दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन कदम भी उठाये गये है;

(ङ) राज्य व्यापार निगम वनस्पति उद्योग जैसे उपभोक्ताओं को आयातित तेल उपलब्ध करता रहा है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को लाइसेंसशुदा उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित करने के लिये आयातित तेल अधिक मात्रा मे दिये जा रहे है। राज्य व्यापार निगम समय-समय पर कुछ चुने केन्द्रों में आवश्यकतानुसार बाजार दखल के उपाय के रूप में खाद्य तेलों की वाणिज्यिक बिक्री भी करता रहा है, ताकि मूल्यों के बढ़ते रुख को रोका जा सके।

(च) जी नहीं। नीति के तौर पर खाद्य तेलों का आयात 2 दिसम्बर, 1978 से राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जा रहा है। तथापि, प्राइवेट पार्टियों को कुछ लाइसेंस दिये गये हैं; ये लाइसेंस कुछ उच्च न्यायालयों के आदेशों के कार्यान्वयन के रूप में और उन प्राइवेट पार्टियों द्वारा दायर की गई अपीलों पर दिये गये अंतिम आदेशों के परिणामस्वरूप दिये गये जिनके लाइसेंस के आवेदन मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात द्वारा अस्वीकार कर दिये गये थे।

चाय बागानों द्वारा चाय की बिक्री

2175. **श्री कृष्णा कुमार गोयल :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चाय बागानों द्वारा चाय की बिक्री के लिये अपनाई जा रही प्रक्रिया से संतुष्ट है;

(ख) क्या इस मामले की जांच करने के लिये कोई समिति गठित की गई थी, यदि हां, तो उस समिति का नाम क्या है और उसका प्रतिवेदन किस तारीख को प्रस्तुत किया गया था; और

(ग) समिति के प्रतिवेदन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और इस्पात तथा खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) चाय बागानों द्वारा बिक्री के वर्तमान तरीके, जिनमे भारत या लन्दन में मुख्य रूप से नीलामी करके बिक्री करने और विदेशी खरीदारों या घरेलू खरीदारों को सीधे बिक्री करने के तरीके शामिल है, एक शताब्दी से भी अधिक समय से चल रहे है और कुल मिलाकर समय की कसौटी पर खरे उतरे है। तथापि, अन्य चाय निर्यातक देशों के साथ प्रतियोगिता बढ़ जाने, आन्तरिक खपत बढ़ जाने और विश्व चाय उद्योग तथा व्यापार के ढांचे में अन्य परिवर्तनों के आ जाने से सरकार ने इस प्रणाली की समीक्षा करना वांछनीय समझा ताकि ऐसे उपचारात्मक उपाय किये जा सकें जो नये परिवर्तनों को देखते हुए आवश्यक हों।

चाय बागानों द्वारा चाय की बिक्री सहित चाय की विपणन प्रणाली की जांच करने के लिए फरवरी, 1978 में श्री पी० एल० टंडन के नेतृत्व में एक समिति नियुक्त की गई थी।

(ग) समिति की सिफारिशों पर सरकार इस समय विचार कर रही है।

जबलपुर में मेडाघाट का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

2176. **श्री सुन्दर शर्मा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर में मेडाघाट का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने की कोई योजना क्रियान्वित की जा रही है;

(ख) क्या कोई अन्य प्रस्ताव भी विचाराधीन है; और

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान कितने पर्यटकों ने मेडाघाट की यात्रा की और उनमें से कितने विदेशी पर्यटक थे ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री ज० बी० पटनायक)) : (क) केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत जबलपुर में मेडाघाट का एक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने की कोई योजना नही है। तथापि, भारत पर्यटन विकास निगम ने पर्यटकों को मेडाघाट, कान्हा नेशनल पार्क और पर्यटक रुचि वाले आस-पास के अन्य स्थानों पर ले जाने के लिए एक परिवहन यूनिट की जबलपुर में स्थापना की है, जिसमें दो कारें और एक कोच शामिल है।

(ख) राज्य सरकार से यह पता चला है कि उन्होने मेडाघाट के लिए एक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित किया है, जिसने मेडाघाट के लिए 29 लाख रुपये की राशि की एक व्यापक विकास योजना तैयार की है। यह स्कीम राज्य सरकार के विचाराधीन है। इस बीच, 1979–80 के दौरान, राज्य सरकार ने मेडाघाट पर पुंज-प्रकाश के लिए 2 लाख रुपये और पहुंच-मार्ग के लिए 75,000 रुपये का प्रावधान किया था। 1980–81 के दौरान, मेडाघाट के सामान्य विकास और पुंज-प्रकाश के लिए 3.50 लाख रुपये की धन-राशि का प्रस्ताव किया गया है। मेड़ाघाट में राज्य सैक्टर के अन्तर्गत सुविधाओं के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना 1978–83 में 9 लाख रुपये का आबंटन किया गया है।

(ग) चूंकि पर्यटकों से संबंधित आंकड़े अखिल भारतीय आधार पर तैयार किये जाते है, इसलिए ऐसे पर्यटकों की संख्या, जिन्होंने पिछले पांच वर्षों के दौरान मेड़ाघाट की यात्रा की और उनमें विदेशी पर्यटकों की संख्या संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है।

Orissa Government request for Air Strips in Orissa

2177. SHRI RASA BEHARI BEHERA: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether Government of Orissa have requested that air strips should be constructed in different places in Orissa;

(b) if so, the names of those places; and

(c) if not, the procedure followed for sanctioning of air strips?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION & LABOUR (SHRI J. B. PATNAIK): (a) No such request has been received by Civil Aviation Department.

(b) Does not arise.

(c) Aerodromes are constructed as per requirements of Indian Airlines and non-cheduled operators subject to availability of resources and plan priorities.

Proposal for Tourist Centres at Kalahandi District (Orissa)

2178. SHRI RASA BEHARI BEHERA: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether any proposal for opening tourist centres at Kalahandi Dis-